Unit - I

लोक वित्त (Public finance)

प्रो॰ लास्की के अनुसार "राज्य समाज के मेहराब की आधारशिला है, जो अनेक मानव - जीवन के रूप में और प्रकृति को साँचे में ढालता है तथा उनके भाग्य की संरक्षणता का दायित्व भी इसी पर है।"

आय एवं व्यय पर कर लगाकर इसे नियन्त्रित किया जाता है। लोक वित्त को राजस्व भी कहा जाता है। लोक वित्त को अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है।

Basic Terms of Public finance
(लोक वित्त की विषय सामग्री)

→ लोक व्यय (Public Expenditure)

→ लोक आय (Public Revenue)

→ लोक ऋण (Public Debt)

→ वित्तीय प्रशासन (financial Administration)

→ राजकोषीय नीति (fiscal Policy)

Nature of Public Finance
(लोक वित्त की प्रकृति)

1) सक्रियकारी वित्त का सिद्धान्त (Theory of Activating finance)

2) नवीन अर्थशास्त्र का सिद्धान्त (Theory of New Economics)

3) लोक वित्त का विशुद्ध सिद्धान्त (Pure Theory of Public finance)

4) क्रियाशील वित्त का सिद्धान्त (Theory of functional finance)

Scope of Public finance (लोक वित्त का क्षेत्र)

1) आय (Income)

2) व्यय (Expenditure)

3) ऋण

4) राजकोषीय नीति

5) राजकोषीय व्यवस्था

Importance of Public Finance
(लोक वित्त का महत्व)

1) मूल्यों को स्थिर करना (fixing of Price)
2) राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना (Determination of National Income)
3) तीव्र आर्थिक विकास (Increase Economic Development)
4) पूर्ण रोजगार की प्राप्ति (full Employment Attainment)
5) आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि (Increase Economic Activity)
6) उत्पादन (Production)

Public Budget
सार्वजनिक बजट

टेलर के अनुसार "बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है।"

किंग के अनुसार " बजट एक प्रशुल्क योजना जिसके द्वारा व्यय को आय से सन्तुलित किया जाता है।"

According to Philip E. Taylor " The budget is the master financial plan of a government."

According to C. I King " The budget is a fiscal plan by which expenditure may be balanced against income."

Budget is a financial statement or quantitative statement prepared prior to a definite period of time, a policy to be persued during that time for the purp of attaining given objective.

बजट एक वित्तीय विवरण और परिमाणिक विवरण है जो एक निश्चित समय से पूर्व बनाया जाता है, जिसमें दिये हुए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति का वर्णन होता है।

Characteristics of Budget (बजट के लक्षण)

1) विवरण

2) निश्चित अवधि से पूर्व

3) वित्तीय बातें

4) सन्तुलित बजट

5) नकदी का आधार

6) वार्षिक आधार

Objectives of Budget (बजट के उद्देश्य)

1) भावी विकास (Future Development)

2) आय - व्यय का अनुमान लगाना (forecasting of Income & Expenditure)

3) नियोजन सम्बन्धी उद्देश्य (Planning Related Objectiv

4) सरकार का अधिकार (Government Rights)

Zero Based Budgeting (ZBB)
शून्य पर आधारित बजट

According to Peter Payerer " Zero based budgeting is an operating planning and budgeting process which requires each manager to justify his entire budget reque[st] in detail from scratch - hence zero base and shifts the burden of proof to each manager to justify why he should spen[d] any money at all."

पीटर पायेरर के अनुसार " शून्य पर आधारित बजटिंग एक संचालित नियोजन एवं बजटिंग प्रक्रि[या] है, जिसमें प्रत्येक प्रबन्धक को अपने सम्पू[र्ण] बजट प्रस्तावों का औचित्य शून्य से बताना होता है तथा प्रत्येक प्रबन्धक पर सबूत का भार डाल दिया जाता है कि उसे कोई धन क्यों व्यय करना चाहिए।"

शून्य पर आधारित बजटिंग को क्रियात्मक, नियोजन एवं बजटिंग प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रबन्धक को अपनी बजट माँग शून्य आधार मानकर बताना है और सिद्ध करने का भार भी प्रत्येक प्रब[न्धक] पर रहेगा कि वह किसी मद पर धन क्यों [व्यय] कर रहा है, 'इस प्रक्रिया में सभी क्रियाओं को निर्णय पैकेज' माना जाता है जिसमें व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा मूल्यांकन कर[के] महत्व के आधार पर स्थान दिया जाता है।

In Zero base budgeting, the budget is broken into units called 'decision packag which are prepared by managers of each level. These packages cover every existing or proposed activity of each department.

Importance of ZBB (महत्व)

1) उद्देश्यों का मूल्यांकन (Evaluation of Objectives)

2) क्रियाओं का विश्लेषण (Analysis of Activities)

3) आवश्यक परिवर्तन (Important Changes)

4) इकाइयों की पहचान (Recognition of Units)

5) निर्णय पैकेज (Decision packages)

Deficit financing
हीनार्थ प्रबन्धन / घाटे की वित्त व्यवस्था

According to National Planning Commission "The term deficit financer is used to denote the direct addition to gross national expenditure through budget deficits, whether the deficits are on revenue or Capital accounts."

In Western Countries deficit financing is and referred to excess of expenditure by government, including capital expenditure over revenue receipts even if it is covered by recepits obtained through loans.

डॉ. राव के अनुसार "जब सरकार जान-बूझकर किसी उद्देश्य से अपनी आय से अधिक व्यय करे और घाटे की पूर्ति देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर करे तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते है।"

घाटे की वित्त व्यवस्था उस स्थिति की व्याख्या करती है जब लोक आय तथा लोक ऋण के मध्य जानबूझर अन्तराल का सृजन किया जाय। हीनार्थ प्रबन्धन का विचार वर्तमान शताब्दी की देन है, हीनार्थ प्रबन्धन का प्रयोग बजट की कमी के रूप में किया जाता है जिसमें आय की तुलना में व्यय की राशी अधिक होती है

Success of Deficit financing
(हीनार्थ प्रबन्धन की सफलता)

1) उत्पादन में वृद्धि (Increase Production)

2) पूँजी की आवश्यकता (Requirement of Capital)

3) समयान्तर (Time Difference)

Effects of Deficit financing (हीनार्थ प्रबन्धन के प्रभाव)

1) विदेशी विनिमय का अभाव (Lack of foreign Exchange)

2) उत्पादन में वृद्धि न होना (No increment in production)

3) रहन-सहन का निम्न स्तर (Low Standard of living)

4) मूल्य स्तर (Price level)

Limitations of Deficit financing (हीनार्थ प्रबन्धन की सीमाएँ)

1) अतिरिक्त क्रय-शक्ति प्राप्त करना
(Providing extra purchasing power)

2) जनता की मनोवृत्ति (Public Mentality)

3) क्रय-शक्ति को निष्क्रिय करना (Inactive purchasing power of public)

4) हीनार्थ प्रबन्धन का उत्पादक कार्यों का प्रयोग
(Use of Deficit financing in production)

Deficit financing in Developed Countries
(विकसित राष्ट्रों में हीनार्थ प्रबन्धन)

(1) नवीन नोट छापकर (Printing of New Notes)

(2) ऋण व बचतें प्राप्त करके (Getting Loans & Savings)

मुद्रा-प्रसार को नियन्त्रित करना
(Control of Deficit financing)

1) उचित मौद्रिक नीति (Perfect Monetary Policy)

2) विनिमय नियन्त्रण (Control over investment)

3) पूँजी व विनियोग पर नियन्त्रण
(Control of Capital & investment)

4) कर नीति (Tax Policy)

UNIT - II

Public Expenditure (लोक व्यय)

According to Dalton "Modern Economist has been slow to correct valgar prejudices on the matter and to place the whole question, from the point of view of principles, upon a rational footing."

The older English writers did not need a theory of expenditure because the theory of government which they held implied a fixed limit to government functions.

डॉल्टन के अनुसार "आधुनिक अर्थशास्त्री ऐसे गलत विचारों को ठीक करने में ढीले रहे हैं और इस प्रश्न को सिद्धान्त के आधार पर विवेकपूर्ण ढंग से रखने में समर्थ हुए हैं।"

लोक व्यय से आशय उन व्ययों से है जो सरकार द्वारा देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण आदि कार्यों में किये जाते हैं। लोक व्यय के द्वारा ही देश में आर्थिक विकास लाने के प्रयास किए जा सकते हैं तथा गरीब वर्ग पर अधिक ध्यान देकर देश में कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि करके देश में जीवन-स्तर को बढ़ाया जा सकता है।

लोक व्ययों की सहायता से ही देश का आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है। लोक व्यय की मात्रा फ्रांस में बढ़कर 10 गुनी, इंग्लैण्ड में 6 गुनी, अमेरिका में 5 गुनी एवं जापान में रु...

हो गयी। भारत में यह व्यय बढ़कर 150 गुना हो गया है।

Importance of Public Expenditure
लोक व्यय का महत्व

1) सन्तुलित विकास (Balanced Development)

2) लोक उद्योगों का विकास (Development of public Industries)

3) कृषि विकास (Developing farming)

4) पूँजी निर्माण (Capital formation)

5) उत्पादन में वृद्धि (Increase production)

लोक व्यय में वृद्धि के कारण
Reasons of Increasing Public Expenditure

1) उद्योगों की स्थापना (Establishment of Industries)

2) उत्पादकों को सहायता (Helpful for producers)

3) मूल्यों में वृद्धि (Increase Prices)

4) सामाजिक सुरक्षा एवं सेवाएँ (Social Safety & Services)

5) सुरक्षा व्ययों में वृद्धि (Increase Expenditure for Safety)

वैगनर के विचार (Views of WAGNER)

वैगनर से कुछ वर्ष पूर्व ऐंजिल्स ने यह नियम प्रतिपादित किया था कि आय में वृद्धि के साथ खाद्यान्न पर आय की लोच गिर जाती है। अन्य शब्दों में, व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ-साथ खाद्यान्न पर होने वाला व्यय कम हो जाता है। व्यक्ति की आय खाद्यान्न पर कम तथा आरामदायक व विलासिता की वस्तुओं पर अधिक धन व्यय करने लगता है।

आर्थिक विकास के कारण जर्मन अर्थशास्त्री वैगनर का विचार था कि सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि होना स्वाभाविक है। वृद्धि का यह अनुपात व्ययों के रूप में परिवर्तित होने पर प्रति व्यक्ति उत्पादन दर को बढ़ा देता है। राष्ट्रीय अनुपात में वृद्धि के साथ-साथ लोक व्ययों में वृद्धि हो जाती है। लोक व्ययों में वृद्धि होने से जनता के आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा देश स्वतः ही प्रगति की ओर अग्रसित होता चला जाता है।

Principles / Canons of Public Expenditure
(लोक व्यय के नियम या सिद्धान्त)

1) मितव्ययिता का सिद्धान्त (Canon of Economy) → समाज के प्रत्येक क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो।

2) आधिक्य का सिद्धान्त (Canon of Surplus) → सरकार को सन्तुलित या अल्प बचत के बजट पर ध्यान देना चाहिए।

3) लाभ का सिद्धान्त (Canon of Benefit)

4) अन्य सिद्धान्त (other Principle)

Classification of Public Expenditure
(लोक व्यय का वर्गीकरण)

(1) आय के आधार पर वर्गीकरण (Revenue Basis)

→ परोक्ष लाभ (Indirect benefit)
→ अलाभकार व्यय (Unprofitable Expenditure)
→ अतिरिक्त आय की प्राप्ति (other Income Generatio

(2) प्रो॰ मिल का वर्गीकरण

→ आवश्यक व्यय (Important Expenditure)
→ ऐच्छिक व्यय (Voluntary Expenditure)

⟨3⟩ प्रों पीगू का वर्गीकरण

→ हस्तान्तरण व्यय (Transfer Expenditure)
→ अहस्तान्तरण व्यय (Retain Expenditure)

⟨4⟩ प्रो॰ रोश्चर का वर्गीकरण

→ आवश्यक व्यय (Important Expenditure)
→ लाभप्रायक व्यय (Profitable Expenditure)
→ अनावश्यक व्यय (Unprofitable Expenditure)

⟨5⟩ श्रीमती हिस्क का वर्गीकरण

→ सुरक्षा व्यय (Safety Expenditure)
→ आर्थिक व्यय (Economic Expenditure)
→ सामाजिक सुरक्षा (Safety of Society)

⟨6⟩ कोहन व प्लेहन का वर्गीकरण

→ विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ (Benefits to Distinguish person
→ समाज को लाभ (Societal Profit)

⟨7⟩ प्रो॰ एडम्स का वर्गीकरण

→ व्यापार एवं वाणिज्य सम्बन्धी (Business & Commercial Relatet)
→ सुरक्षा व्यय (Safety Expenditure)
→ विकास व्यय (Development Expenditure)

⟨8⟩ प्रो॰ शिराज का वर्गीकरण

→ प्राथमिक व्यय (Primary Expenditure)
→ गौण व्यय (Secondary Expenditure)

⟨9⟩ प्रो॰ जे॰ के मेहता का वर्गीकरण

→ परिवर्ती व्यय (Variable Expenditure)
→ अपरिवर्ती व्यय (Invariable Expenditure)

⟨10⟩ प्रशासनिक इकाई का आधार

→ स्थानीय व्यय (Local Expenditure)
→ प्रान्तिय व्यय (Regional Expenditure)
→ केन्द्रीय व्यय (Central Expenditure)

⟨11⟩ डाल्टन का वर्गीकरण

→ सामाजिक सुरक्षा (Society Safety)
→ ऋण सम्बन्धी (Related loans)
→ विकास व्यय (Development Expenditure)

⟨12⟩ अमरीकी वर्गीकरण

→ राष्ट्रीय सुरक्षा (National Safety)
→ श्रम कल्याण (Labour Welfare)
→ कृषि (farming)

UNIT - III

लोक आय (PUBLIC REVENUE)

The Revenues from different sources received by the govt called public revenues. Public Revenue consists of taxes, revenue from administrative activities like fines, fees, gifts & grants. Revenues are not repayable. It is an important tool for the fiscal policy of the public & its is the opposite factor of public spending.

राजस्व के अध्ययन में लोक आय का वही स्थान है जो अर्थशास्त्र में उत्पादन का है। जिस प्रकार उपभोग हेतु उत्पादन होना आवश्यक है, उसी प्रकार लोक व्यय हेतु लोक आय का पर्याप्त होना आवश्यक है। लोक आगम सरकार के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोक आय सरकारी कार्यों को प्रगति प्रदान करती है राजस्व रूपी यन्त्र में यह तरलता व चिकनाहट बनाये रखती है। वर्तमान समय में राज्य के कार्यों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण लोक आय के नवीन स्त्रोतों को आयाम दिया है।

प्रो. डी. मार्को के अनुसार "कर वह मूल्य है जोकि प्रत्येक नागरिक सरकार को सामान्य लोक सेवाओं की लागत के बदले में जिसे वह उपभोग करेगा, देता है।"

Importance of Public Revenue

1) Planned Economic Development
2) Reducing Economic Inequalities
3) Protection of infant (शिशु) industries
4) Discourage the production of harmf goods

Definition of Public Revenue

According to De Marco "The tax is the price which each Citizen pays to the State to cover his shares of the cost of the general public Services which he will Consume."

लोक आय के स्त्रोत
(Sources of Public Revenue)

⟨A⟩ कर - आय स्त्रोत (Tax-Revenue Sources)

→ कर एक अनिवार्य भुगतान है।
→ कर के बदले विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता।
→ कर की आय का सामान्य हित में उपयोग।

(B) गैर-कर आय स्रोत (Non-Tax Revenue Sources)

→ फीस
→ जुर्माना एवं दण्ड
→ विशेष निर्धारण

करों के प्रकार (Types of Taxes)

(A) भुगतान पर आधार (Based on Payment)

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)	अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
→ आय	→ बिक्री कर
→ सम्पत्ति	→ आयात-निर्यात कर

(B) कर की दर के आधार पर करों के प्रकार
(Types of Taxes on the basis of Rate of Tax)

प्रगतिशील कर (Progressive Tax)	अधोगामी कर (Degressive Tax)	प्रतिगामी कर (Regressive Tax)
→ आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ना।	→ आनुपातिक व प्रगतिशील दोनों का मिश्रण	→ आय बढ़ने के साथ-साथ कर की दर कम होना।

⟨C⟩ निर्धारण आधार पर करों के प्रकार
(Kinds of Taxes on the basis of Determination)

→ मूल्यानुसार कर (Ad-Volaram Tax)
→ व्यक्तिगत कर (Personal Tax)
→ विशिष्ट कर (Specific Tax)

करारोपण (Taxation)

डाल्टन के अनुसार "कर लोक सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, भले ही इनके बदले में करदाता को उतनी सेवाएँ प्रदान की गयी हों या नहीं।"

कर जनता पर लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है जिसे देना आवश्यक माना जाता है। वर्तमान युग में, करारोपण सरकारी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन काल में प्रत्येक कर बुरा माना जाता था परन्तु वही कर आज की अर्थव्यवस्था वित्तीय ढाँचे का एक शक्तिशाली अस्त्र बन चुका है। सरकार पहले व्यय का अनु[illegible] करती है।

सरकार की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी आय होती है, जिसका राजस्व में महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार के कर्तव्यों वृद्धि होने से लोक व्यय की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और उसे पूरा करने लिए जनता पर कर लगाये जाते हैं [illegible]

जनता को सहन करना ही होता है।

According to Dalton "The best system is that in which the cost of collection in proportion to the revenue collected is minimum."

Taxation is an act of production and therefore, one must affect as much econom production as possible. The tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid, ought all to be clear and plain to the contribution and to every person.

करारोपण के उद्देश्य (Objective of Taxation)

1) आय प्राप्त करना (Income Generation)

2) न्यायोचित वितरण व्यवस्था (Legal Distribution System)

3) नियमन एवं नियन्त्रण (Regulation & Control)

4) राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase National Income)

करारोपण के सिद्धान्त (Principles of Taxation

1) निश्चितता का सिद्धान्त (Canon of Certainty)

2) समानता का सिद्धान्त (Canon of Equity)

3) सुविधा का सिद्धान्त (Canon of Convenience)

4) मितव्ययिता का सिद्धान्त (Canon of Economy

5) लोच का सिद्धान्त (Canon of Elasticity)

6) उत्पादकता का सिद्धान्त (Canon of producti

भारत में एक अच्छी कर-प्रणाली के गुण (Merits of a Good Tax System in india)

1) अधिकतम सामाजिक लाभ (Increase Soci Welfare)

2) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर (Direct or Indirect T

3) करारोपण के सिद्धान्तों के अनुकूल (Principl of favourable Taxation)

4) लोच (Flexibility)

5) उत्पादकता (Production)

6) निश्चितता (fixed Time Period)

7) समानता सिद्धान्त (Principle of Equality)

भारतीय कर-प्रणाली के दोष
(Defects of Indian Tax System)

1) कर की चोरी (Tax Evasion)

2) असन्तुलित (Imbalanced)

3) न्यायशीलता का अभाव (Lack of fairness)

4) अनिश्चित (Not fix)

विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में कर-पद्धति के उद्देश्य
(Objectives of Tax System in Developing Economy)

1) पूँजी निर्माण (Capital formation)

2) आर्थिक साधनों में गतिशीलता (Mobility in Economic Resources)

3) देश में समृद्धि (Prosperity in Country)

4) उत्पादक विनियोग (Producers investment)

Direct Tax	Indirect Tax
वे टैक्स हैं जो सरकारें सीधे जनता से लेती हैं।	वे टैक्स हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पर जनता सरकार को देती है।
• Income Tax → Income Tax हर एक व्यक्ति, जिसकी आय Taxable limit से ज्यादा होती है। भारत में २.5 लाख रु. से ज्यादा की सलाना आय पर इनकम टैक्स देना होता है।	• Sales Tax → वस्तुओं को बेचने पर लगने वाले टैक्स।
• Capital Gain Tax → इसके तहत अगर आपकी संपत्ति, शेयर, बॉन्ड्स या महंगी वस्तुओं को बेचकर आप मुनाफा कमाते हैं तो आपको ये टैक्स सरकार को चुकाना होगा।	• Value Added Tax (VAT) → ज्यादातर राज्य सरकारें वस्तुओं और सेवाओं पर VAT भी लगाती हैं। VAT की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-२ है।
• Securities Transaction Tax → इसके तहत स्टोक Exchange में हर Transaction पर आपको टैक्स देना होता है।	• Service Tax → सभी सेवाओं पर लगने वाले टैक्स को Service Tax कहते हैं। अभी भारत में आपको हर सेवा पर 15 फीसदी Service Tax देना पड़ता है।
	• Custom Duty (... → भारत में विदेश से आयात होकर

- Corporate Tax → जिसके तहत देश भर की कंपनियां अपनी आय पर सरकार को टैक्स देती है।

आने वाले सामानों पर सरकार Custom Duty लगाती है।

- Excise Duty → देश में बनने वाले उत्पादों पर लगाने वाले टैक्स को Excise duty कहते है।

वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी)
Goods & Service Tax (GST)

जीएसटी (GST) भारत के कर संरचना में सुधार का एक बहुत बड़ा कदम है। यह एक परोक्ष कर है। वस्तुतः जीएसटी एक एकीकृत कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर ही लगाया जाता है। विश्व के 150 से अधिक देशों द्वारा जीएसटी अपनाए जाने के कारण भारत के लिए इसे अपनाना आवश्यक हो चुका था। अब तक भारत सहित 160 देशों ने जीएसटी अपनाया है। जीएसटी लागू होने से सम्पूर्ण भारत एकीकृत बाजार में परिवर्तित हो गया है अब सम्पूर्ण भारत में एक ही प्रकार का परोक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगेगा।

जीएसटी की विशेषताएँ (Features of GST)

→ One Tax rate across the Country

→ No tax on Tax

→ Taxable Events Supply of Goods or Service

→ No differentiation in Goods & Service

→ free flow of Credit

जीएसटी के लाभ (Advantages of GST)

* कर की दर और ढाँचे में सन्तुलन (Balanced Structure & Rate of Tax)
* व्यापार में एक स्वस्थ प्रतियोगिता (Healthy Competition in Business)
* पारदर्शिता (Transparency)
* उच्चतर धन संचय (Accumulation of Wealth)
* पारदर्शी कर व्यवस्था (Transparent Tax System)

करदान क्षमता
(Taxable Capacity)

According to Dalton "In the interest of clear thinking it would be well that the phrase taxable capacity should be banished (over) from all serious discussion of public finance."

Taxable capacity of different section of the community may be said to refer in the degree of taxation, broadly speaking beyond which productive effort and efficiency as a whole begin to suffer. Relative taxable capacity is a reality which can however be equally will expressed other terms while absolute taxable capacity is a myth.

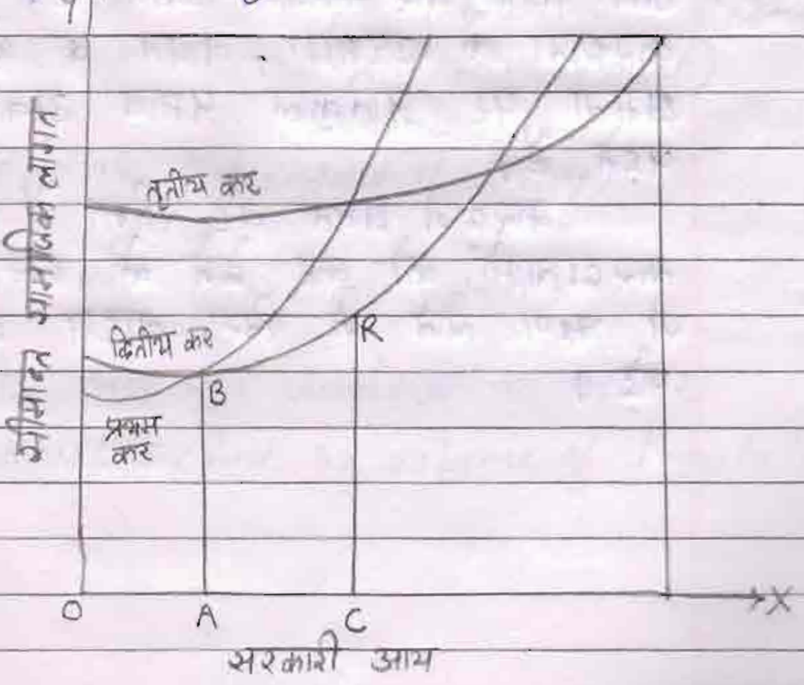

डाल्टन के अनुसार "स्पष्ट विचारों के हित में यह उपयुक्त होगा कि करदान क्षमता वाक्यांश को ही राजस्व के समस्त गम्भीर वाद-विवाद में से निकाल दिया जाना चाहिए।"

मैसन "करदान क्षमता की सीमा उस बिन्दु पर आती है जहाँ पर करारोपण से उत्पादन प्रभावित होता है।"

करदान क्षमता कुल उपयोग पर कुल उत्पादन का आधिक्य है। यह वह अधिकतम राशि होती है जोकि इस देश के नागरिक बिना आनन्द रहित तथा पददलित जीवन बिताये और आर्थिक संगठन को बहुत उथल-पुथल किये बिना ही राजकीय अधिकारियों के व्यय की ओर अंशदान करते हैं। जब कोई कर लगाया जाता है, तो उससे करदाता के उपभोग, बचत व विनियोग क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ते हैं।

करदान क्षमता वह सीमा है जब करदाताओं को कर देने के लिए बैंकों से ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़े।

करदान क्षमता का महत्व
(Importance of Taxable Capacity)

→ उत्पादन की प्रतिक्रिया (Reaction of Productivity)
→ संकटकाल (Crisis Time)
→ आर्थिक क्षमता (Economic Efficiency)
→ नागरिकों की सन्तुष्टि (Satisfaction of Citizens

करदान क्षमता को निर्धारित करने वाले तत्व
(factors Determining Taxable Capacity)

→ सामाजिक कल्याण (Social Welfare)
→ राष्ट्र का आर्थिक विकास (National Economic Development)
→ जीवन स्तर (Standard of Living)
→ कर प्रणाली (Taxation System)
→ राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या का आकार (National Income or volume of Population)

करदान क्षमता की माप
(Measurement of Taxable Capacity)

⟨1⟩ कुल आय विधि
(Aggregate Income Method)

⟨2⟩ उत्पादन विधि
(Production Method)

भारत में करारोपण का निम्न स्तर
(Low Level of Taxation in India)

⟨1⟩ जनता का निम्न जीवन स्तर होना
(Low Standard of Living of Public)

⟨2⟩ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कम होना (Minimum International Business)

करदान क्षमता की माप
(Measurement of Taxable Capacity)

⟨1⟩ कुल आय विधि
(Aggregate Income Method)

⟨2⟩ उत्पादन विधि
(Production Method)

भारत में करारोपण का निम्न स्तर
(Low Level of Taxation in India)

⟨1⟩ जनता का निम्न जीवन स्तर होना
(Low Standard of Living of Public)

⟨2⟩ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कम होना (Minimum International Business)

करपात / कर-भार

Taxation

According to Dalton "The problem of the incidence of a tax is Commonly Conceived as the protection of who pays it."

The term incidence as Commonly used to the location of the ultimate or the direct money burden of the tax as such. Persons who pay a tax are often less injured by its imposition than those who pay no portion.

प्रो० मुसग्रेव के अनुसार "कर भार शब्द जिसका साधारणतः प्रयोग होता है, कर के अन्तिम या प्रत्यक्ष मौद्रिक भार के स्थान से सम्बन्धित होता है।"

जो व्यक्ति कर का भुगतान करे उस पर कर का दबाव पड़ता है और जो व्यक्ति कर के भार की समस्या अन्तिम रूप से कर का भार सहन करे उसे कर-भार या करापात कहा जाता है।

करापात धारणा का महत्व
(Importance of Concept of Incidence of Taxation)

1) किसी व्यक्ति पर कर लगाया जा सकता है।

2) वह व्यक्ति कर को दूसरे व्यक्ति पर स्थानान्तरित कर सकता है।

3) कर का वहन दूसरे व्यक्ति द्वारा सम्भव हो सकता है।

करापात के अध्ययन में कठिनाइयाँ
(Problem of Incidence of Taxation)

1) करापात व कर के प्रभावों में भेद करना कठिन

2) तुलनात्मक धारणा

3) मूल्यों (Value) में उतार चढ़ाव

UNIT - IV

World Bank, RBI

लोक ऋण (Public Debt)

According to J.K Mehta "For the King borrowed money on their personal Credit and not on the Credit of the Government and his successors were not bound to pay off that debts."

Public Debt is a Comparatively modern phenomenon and has come into existence with the development of democratic form of governments in the world. funds borrowed by the State are to be spent for the benefit of the Community. The proceeds private loans are used for the benefit of the borrowed only.

प्रो॰जे॰के॰मेहता के अनुसार "लोक ऋण अपेक्षाकृत आधुनिक घटना है तथा विश्व में जनतान्त्रिक सरकारों के विकास के साथ व्यवहार में आया है।"

लोक ऋण वह ऋण है, जिसके भुगतान हेतु कोई सरकार अपने देश के नागरिकों या दूसरे देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होती है। युद्धकालीन एवं संकटकालीन स्थिति में सरकार को करारोपण के स्थान पर ऋण लेना अनिवार्य हो जाता है।

लोक ऋणों के महत्व
(Importance of Public Debts)

1) आर्थिक कारण (Economic Cause)

2) धन की अधिक आवश्यकता होने पर
(To fulfill the need of Money)

3) राज्य के कार्यों में वृद्धि
(Work Progress in State Works)

4) बचत का अभाव (Reason of Saving)

5) आर्थिक विकास (Economic Development)

लोक ऋणों का वर्गीकरण
(Classification of Public Debts)

⟨1⟩ ऋण आधार (Basis of Loan)

→ आन्तरिक ऋण (Internal Debt)

→ बाहरी ऋण (External Debt)

⟨2⟩ उत्पत्ति की दृष्टि से (Production Basis)

→ उत्पादक ऋण (Productive Debt)

→ अनुत्पादक ऋण (Unproductive Debt)

<3> समय की दृष्टि से (Time Basis)

→ अल्पकालीन ऋण (Short term Debt)

→ दीर्घकालीन ऋण (Long term Debt)

<4> शोधन ऋण की दृष्टि से (Redemption Basis)

→ शोध्य ऋण (Redeemable Debts) ⇒ Payment till due date

→ अशोध्य ऋण (Irredeemable Debts) ⇒ There is no limit of payment

<5> स्वेच्छा की दृष्टि से

→ ऐच्छिक ऋण (Voluntary Debt)

→ बलात ऋण (Compulsory Debt)

<6> ~~पुनरुत्पादक ऋण~~ सम्पत्ति की दृष्टि से (Property Basis)

→ पुनरुत्पादक ऋण (Reproductive Debt)

→ मृतक बोझ ऋण (Dead Weight Debt)

⟨7⟩ अन्य वर्गीकरण (other Classification)

→ सूद सहित एवं सूद रहित ऋण
(With or without Interest Debts)

→ लॉटरी ऋण (Lottery Debts)

लोक ऋण प्रबन्ध के सिद्धान्त
(Principles of Public Debt Management)

- विनियोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति
(Satisfaction of the Needs of Investors)
- लोक ऋण नीति का प्रशुल्क व मौद्रिक नीति में समन्वय (Co-ordination of Public Debt Policy with fiscal & Monetary Policy)
- परिपक्वता एवं वितरण
(Maturity & Distribution)
- अल्पकालीन ऋणों का दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तन (Conversion of Short term loans into Long term loans)

लोक ऋणों के लाभ
(Merits of Public Debts)

- आर्थिक विकास (Economic Development)
- उद्योगों को प्रोत्साहन (Industrial Motivation)
- सामाजिक कार्य (Social Work)
- प्राकृतिक विपदाओं पर विजय (Victory over Natural Disasters)
- सुरक्षा विनियोग (Safe investment)
- बैंकों का विकास (Development of Banks)
- गैर आर्थिक लाभ (Economic Benefit)
- मूल सुविधाओं का विकास (Infrastructure Development)
  ⇒ सड़क, रेल, विद्युत आदि।

लोक ऋणों की हानियाँ
(Demerits of Public Debts)

- सरकार के दिवालिया होने का डर
  (Fear of Government Insolvancy)
- अपव्यय (Wastage)
- साधनों का शोषण (Exploitation of Tools)
- ऋण लेने की आदत (Habit of taking loan / Credit
- जनता पर भार (Public Burden)
- अर्थव्यवस्था को कमज़ोर (Weak Economy)
- संकट (Problems)

UNIT - V

भारतीय लोक वित्त / राजस्व
Indian Public finance

According to Robert Garren " A federation is a form of government in which Sovereignity & political power is divided between the Central & local government, so that each of them, with in its own sphere is independent of the other."

The ideal allocation of resources between the federation and the States should be in accordance with the principle of the national minimum for people living int different States. This can be achieved through transferences from rich areas to poor areas in a federal State.

आर. एन. भार्गव के अनुसार " संघीय वित्त से आशय केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों एवं उन दोनों के मध्य समन्वय से लगाया जाता है।"

किसी भी देश में दो प्रकार की शासन व्यवस्था हो सकती है। जब देश में केवल एक ही सरकार हो तो उसे 'एकाकी प्रणाली' कहते है, और जब एक से अधिक सरकारें हो, तो उसे 'संघीय शासन' कहते है। एकात्मक शासन व्यवस्था में सम्पूर्ण देश की शासन

व्यवस्था एक ही सरकार के हाथ में होती है। इसके विपरीत, संघीय शासन प्रणाली में केन्द्रीय सरकार के अलावा प्रान्तीय स्तर पर राज्यों सरकारें होती हैं जो अपनी सीमा में अपनी इच्छानुसार शासन व्यवस्था का संचालन करने में स्वतन्त्र होती है।

भारतीय राजकोषीय संघ की स्थापना गैर-एकत्रीकरण की प्रक्रिया से प्रारम्भ हुई। मुगल शासकों ने वित्तीय प्रशासन की केन्द्रीय व्यवस्था स्थापित की, जिसे ब्रिटिश शासकों ने सुदृढ़ बनाया। जब किसी देश में केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त अन्य राज्य सरकारें भी होती हैं, जिन्हें अपने राज्य की सीमा में इच्छानुसार शासन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है किन्तु कुछ मामलों में केन्द्र से सम्बन्धित होती है तो यह शासन-व्यवस्था संघीय माना जाती है।

संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएँ
(Characteristics of federal finance)

1) विभाजन (Dividation)

2) सर्वोच्च विधान (Supreme Legislation)

3) समान अधिकार (Equal Rights)

4) कार्यों का विभाजन (Distribution of Work)

संघीय कार्य क्षेत्र
(federal Scopes)

1) वे कार्य जिनका महत्व देश के लिए है।

2) वे कार्य जिनका केवल स्थानीय महत्व ही होता है।

forms of federal finance
(संघीय वित्त व्यवस्था के रूप)

(1) एकात्मक वित्त → इस व्यवस्था के अन्तर्गत देश की समस्त आय एवं समस्त व्यय को केन्द्रीय सरकार के कोष से लिया जाता है।

(2) संघीय वित्त → इसके अन्तर्गत आय-व्यय की समस्त मदों को केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकारों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है और विभिन्न सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होती हैं।

संघीय वित्त व्यवस्था के सिद्धान्त
(Principles of federal finance)

- एकरूपता का सिद्धान्त (Principle of Uniformity)
- हस्तान्तरण का सिद्धान्त
  (Principle of Transference)
- संघीय प्रबन्ध सिद्धान्त
  (Principle of federal Supervision)

भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था का इतिहास
(History of federal finance in india)

⇔ स्वतन्त्रता से पूर्व → सन् 1871 तक केन्द्रीकरण का काल रहा जिसमें कुछ दोष पाये जाने से सन् 1871 में लॉर्ड मेयो की योजना के अन्तर्गत 1871-1919 तक विकेन्द्रीकरण का काल रहा। सन् 1935 में प्रान्तीय स्वायत्तता की नींव रखी गयी। भारत के संविधान में संघ एवं राज्य सरकारों के मध्य आय के स्रोतों का वितरण निम्न प्रकार किया गया है -

- संघीय साधन → रेल, डाक व तार, निगम कर सीमा कर आदि।

- राज्य साधन → विक्रय कर, मनोरंजन कर, कृषि आय कर आदि।

- विभाजित साधन → आय पर लगाये गये कर, उत्पादन कर आदि।

- सम्पूर्ण प्राप्ति राज्य सरकार को देना → मृत्यु कर, यात्रियों व वस्तुओं पर लगाये गये सीमान्त कर आदि।

⇔ स्वतन्त्रता के बाद → देश विभाजन व देशी रियासतों के एकीकरण के फलस्वरूप संघीय वित्त व्यवस्था में उथल-पुथल होना स्वाभाविक था। इस समस्या का अस्थायी हल निकालने हेतु सन् 1948 में 'सरकारी समिति' तथा सन् 1950 में 'देशमुख एवार्ड' का गठन किया गया था लेकिन यह प्रयास अधिक कारगार सिद्ध न हो सके।

वित्तीय समायोजन
(financial Adjustment)

संघीय शासन-व्यवस्था में संघ सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय समायोजन होना चाहिए। वित्तीय समायोजन सम्बन्धी मुख्य नियम निम्न प्रकार है -

⟨1⟩ अनुपूरक कर (Supplementary Taxes)

⟨2⟩ राज्यों का संघ सरकार के लिए अंशदान (Contribution of Centre by States)

⟨3⟩ कर प्राप्ति का वितरण (Distribution of Tax Revenue)

⟨4⟩ संघीय अनुदान (federal Grant-in-aid)

भारत में वित्तीय समायोजन (financial Adjustment In India)

- आय-कर एवं उत्पादन कर (Income Tax & Production Tax)
- सहायक अनुदान (Supportive Grants)
- अधिभार (Surcharge)
- ऋण प्राप्त करना (Getting Loan)

वित्तीय समायोजन के सिद्धान्त
(Principles of financial Adjustment)

→ प्राकृतिक साधन
(Natural Resources)

→ जलवायु व सिंचाई
(Climate & Irrigation)

→ जनसंख्या का आकार
Size of Population

→ आर्थिक विकास की स्थिति
(Situation of Economic Development)

→ कर देय क्षमता
(Ability of Tax Pay)